eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 07, July 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.21744704

भारतीय उच्च शिक्षा में छात्राओं के नामांकन की वर्तमान स्थिति, चुनौतियां और सम्भावनाएं: एक विशलेषणात्मक समीक्षा

डॉ० मालती वर्मा[1]
[1]एसोसिएट प्रोफेसर, प्रशिक्षण विभाग, ए०एन०डी० कॉलेज, कानपुर, उ0प्र0

Received: 21 July 2026 Accepted & Reviewed: 25 July 2026, Published: 31 July 2026

Abstract

किसी भी राष्ट्र के सतत विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक समृद्धि की आधारशिला उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है। उच्च शिक्षा न केवल व्यक्तिगत कौशल का विकास करती है, बल्कि समाज में लैंगिक समानता (Gender Equality) और महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) का सबसे प्रभावी उपकरण भी है। ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज में महिलाओं की उच्च शिक्षा तक पहुँच सीमित रही है, जिसका मुख्य कारण पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, आर्थिक सीमाएं और सुरक्षा संबंधी चिंताएं रही हैं। हालांकि, पिछले दो दशकों में भारत सरकार के विभिन्न नीतिगत प्रयासों, जैसे– राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020), तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में छात्रवृत्ति योजनाएं और सामाजिक जागरूकता के कारण उच्च शिक्षा में छात्राओं के नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। यह शोध पत्र अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) के हालिया आंकड़ों के आलोक में छात्राओं के नामांकन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करता है।

मुख्य शब्दः– नामांकन, उच्च शिक्षा, विशलेषणात्मक, चुनौतियां, सम्भावनाएं, नीतिगत सुझाव

Introduction

किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास की धुरी उसकी शिक्षा प्रणाली होती है। उच्च शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम होती है, बल्कि यह लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का सबसे सशक्त उपकरण भी होती है। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय समाज में महिलाओं की शिक्षा तक पहुँच सीमित रही है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद, विशेषकर पिछले दो दशकों में, इस परिदृश्य में व्यापक बदलाव आया है। वैश्वीकरण, आर्थिक विकास और सरकार की समावेशी नीतियों ने महिलाओं को चारदीवारी से निकालकर विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों तक पहुँचाया है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (AISHE) के हाल में आंकड़े यह दर्शाते हैं कि उच्च शिक्षा में श्लैंगिक समानता सूचकांक (Gender Parity Index & GPI) में निरंतर सुधार हुआ है। लेकिन, संख्यात्मक वृद्धि के बावजूद, विषय–चयन में लैंगिक रूढ़िवादिता (Gender Segregation in Stream), बीच में पढ़ाई छोड़ना (Dropout Rate), और ग्रामीण–शहरी असमानता जैसी चुनौतियाँ आज भी सभी स्थानों पर विद्यमान हैं। प्रस्तुत शोध पत्र उच्च शिक्षा में छात्राओं के नामांकन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा तथा इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं का विश्लेषण करते हुये भावी सुझाव भी प्रस्तुत करता है।

उच्च शिक्षा में छात्राओं के नामांकन की वर्तमान स्थिति (Current Status of Female Enrollment)

सकल नामांकन अनुपात (GER) में सुधार– पिछले एक दशक में भारतीय उच्च शिक्षा की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक महिलाओं के सकल नामांकन अनुपात में निरंतर वृद्धि होना है। प्राप्त आधिकारिक सरकारी आंकड़ों के अनुसार, उच्च शिक्षा (18–23 वर्ष आयु वर्ग) में महिलाओं का GER अब पुरुषों के मुकाबले में उसके समकक्ष स्तर पर आ गया है। वर्ष 2011–12 में जहाँ छात्राओं का GER मात्र 19.4%

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 07, July 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.21744704

था, वहीं हाल के वर्षों (AISHE रिपोर्ट्स) के अनुसार यह बढ़कर 27.9% से 28.4% के स्तर को पार कर गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों से छात्राओं का सकल नामांकन अनुपात छात्रों (Male GER) की तुलना में अधिक नामांकित हो रहा है। जो उच्च शिक्षा के प्रति बालिकाओं की बढ़ती आकांक्षाओं को दर्शा रहा है।

विभिन्न विषयों (जैसे– मानविकी, विज्ञान, वाणिज्य और STEM) में छात्राओं के नामांकन के बदलते पैटर्न का विश्लेषण करना।

लैंगिक समानता सूचकांक (Gender Parity Index & GPI)– लैंगिक समानता सूचकांक (GPI) उच्च शिक्षा में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात को मापता है। (1 का अर्थ पूर्ण समानता है, 1 से अधिक का अर्थ महिलाओं की अधिक संख्या है)। वर्ष 2011–12 में भारत का उच्च शिक्षा का GPI 0.88 था, जिसमें पुरुषों की तुलना में महिलाएं काफी पीछे थीं। लेकिन वर्तमान समय में राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा में छात्राओं का नामांकन GPI 1.05 तक पहुँच चुका है जिसके परिणामस्वरूप यह ज्ञात होता है कि अब उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं की संख्या छात्रों के सापेक्ष अधिक हो रही है।

विषय–वार नामांकन का प्रतिरूप (Stream-wise Enrolment Pattern)– वर्तमान समय में वैसे तो छात्राओं के नामांकन में बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन विभिन्न विषयों (Streams) के अन्तर्गत अभी निम्नलिखित रूप से असंतुलन देखा जा सकता है:–

1. **कला और मानविकी (Arts & Humanities)**:– छात्राओं का सबसे अधिक नामांकन कला और सामाजिक विज्ञान विषयों में है, जहाँ वे कुल छात्रों का लगभग 52% से 55% हिस्सा छात्राओं का होता है।

2. **विज्ञान और चिकित्सा (Science & Medical Sciences)**:– सामान्य विज्ञान (B.Sc, M.Sc) और नर्सिंग/आयुष जैसे चिकित्सा पाठ्यक्रमों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तेजी से बढ़ा है।

3. **STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित):–** तकनीकी शिक्षा (Engineering & B-Tech) और प्रबंधन (Management) में अभी भी लैंगिक अंतराल मौजूद है। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में छात्राओं का नामांकन कुल सीटों का लगभग 29% से 32% के आसपास ही सिमटा हुआ है, हालांकि वैश्विक औसत की तुलना में भारत में STEM में महिलाओं का यह अनुपात बेहतर माना जाता है।

उच्च शिक्षा में छात्राओं के समक्ष प्रमुख चुनौतियां– नामांकन के सकारात्मक आंकड़ों के बावजूद, छात्राओं को अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने और उसे रोजगार में बदलने के मार्ग में कई जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:–

1. **सामाजिक–सांस्कृतिक चुनौतियाँ:–** ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में आज भी पितृसत्तात्मक सोच हावी है। बेटियों की कम उम्र में शादी करने का दबाव उच्च शिक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। कई समाजों में यह माना जाता है कि महिला की उच्च शिक्षा पर निवेश करने से आर्थिक लाभ नहीं होता, क्योंकि वह विवाह के बाद दूसरे घर चली जाती है। ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में आज भी बेटों के लिये उच्च शिक्षा को दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखा जाता है।

2. **आर्थिक बाधाएँ:'–** जब किसी सीमित आय वाले परिवार को बेटे और बेटी में से किसी एक को उच्च शिक्षा दिलाने का विकल्प चुनना होता है, तो प्राथमिकता प्रायः बेटे को दी जाती है। उच्च शिक्षा की बढ़ती

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 07, July 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.21744704

फीस, हॉस्टल का खर्च और महंगी किताबें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को स्थानीय या सस्ते गैर व्यावसायिक कॉलेजों में प्रायः भेज दिया जाता है इसके अलावा पुस्तकों, परिवहन, सुरक्षा व्यवस्था पर होने वाला खर्च गरीब परिवारों के लिये बोझ बन जाता है।

3. ढांचागत और सुरक्षा संबंधी चिंताएँः– विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्राओं के लिए सुरक्षित परिवहन, पर्याप्त महिला शौचालय और सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इसके अतिरिक्त, परिसरों के भीतर और बाहर सुरक्षा की चिंता (जैसे छेड़छाड़ और उत्पीड़न) के कारण कई माता–पिता अपनी बेटियों को दूर के शहरों में पढ़ने के लिये नहीं भेजते है। कॉलेज की दूरी और विश्वसनीय तथा सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन का न होना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है।

5. पारिवारिक दबावः– उच्च शिक्षा में यह एक गंभीर समस्या है। स्नातक स्तर पर तो छात्राएं भारी संख्या में नामांकन लेती हैं, लेकिन स्नातकोत्तर (Postgraduate) और पीएचडी (Ph.D.) स्तर तक पहुँचते–पहुँचते उनकी संख्या तेजी से घटने लगती है। पारिवारिक दबाव, विवाह और मातृत्व इत्यादि कारणों से उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान में छात्राओं की नामांकन सख्या कम हो जाती है।

नामांकन में वृद्धि करने के लिये सरकारी नीति एवं योजनाः– भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने छात्राओं के नामांकन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैंः–

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020):– इस नीति में श्समानता और समावेशनश पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों की छात्राओं के लिए 'जेंडर इंक्लूजन फंड' (Gender Inclusion Fund) की व्यवस्था की गई है। शिक्षा में नामांकन को केवल मातृात्मक न रखकर गुणात्मक बनाने हेतु बहुत सारे उपाय किये गये है जिसमें ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति और अल्पसंख्यक तथा ई०डब्लू०एस० इत्यादि समुदायें की छात्राओं को विशेष उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनाओं का दायरा बढ़ाना चाहिए ताकि ऐसे परिवारों का आर्थिक बोझ कम हो सके।

प्रमुख सुझावः– छात्राओं के नामांकन के लिये वर्तमान में निम्नलिखित सुझावों को अपनाया जा सकता है जो इस प्रकार हैः–

1. सुरक्षित बुनियादी ढांचारू सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनिवार्य रूप से महिला हॉस्टल्स, सुरक्षित परिवहन और आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) को सुदृढ़ किया जाए।

2. करियर काउंसलिंग और मेंटरशिपरू स्कूलों और कॉलेजों के स्तर पर छात्राओं के लिए विशेष करियर काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाने चाहिए ताकि वे पारंपरिक विषयों से हटकर STEM और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन कर सकें।

3. वित्तीय सहायता का विस्तारू ग्रामीण और वंचित वर्ग की छात्राओं के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति और कम ब्याज पर शैक्षिक ऋण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

4. लचीली शिक्षा प्रणालीरू दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा (Distance and Online Learning) के माध्यम से कामकाजी महिलाओं और माताओं के लिए उच्च शिक्षा के दरवाजे हमेशा खुले रखे जाने चाहिए। संक्षेप में, उच्च शिक्षा में महिलाओं को केवल नामांकित करना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें एक ऐसा सक्षम वातावरण

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 07, July 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.21744704

प्रदान करना आवश्यक है जहां वे अपनी शिक्षा का उपयोग देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में प्रभावी ढंग से कर सकें।

निष्कर्ष (Conclusion)– निष्कर्षतः, भारतीय उच्च शिक्षा में छात्राओं के नामांकन की स्थिति संतोषजनक गति से आगे बढ़ रही है। सकल नामांकन अनुपात में पुरुषों के मुकाबले छात्राओं का आगे निकलना और लैंगिक समानता सूचकांक का 1 से ऊपर जाना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारत की बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अत्यधिक लालायित और सक्षम हैं। हालांकि, इस संख्यात्मक प्रगति को वास्तविक महिला सशक्तिकरण और देश के आर्थिक विकास में बदलने के लिए सामाजिक रूढ़ियों, सुरक्षा की कमियों और STEM क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व जैसी गंभीर चुनौतियों का समाधान करना होगा।

केवल नीतियों के निर्माण से बदलाव संभव नहीं हैय इसके लिए स्थानीय प्रशासन, विश्वविद्यालयों, परिवारों और उद्योगों को मिलकर एक सुरक्षित तथा सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना होगा। जब उच्च शिक्षा प्राप्त नारी देश के कार्यबल (Workforce) में सक्रिय भूमिका निभाएगी, तभी भारत एक विकसित और समतामूलक राष्ट्र बनने के अपने सपने को साकार कर सकेगा।

संदर्भ सूची–

1. अग्रवाल, पवन (2019). भारतीय उच्च शिक्षाः चुनौतियां और अवसर। नई दिल्लीः सेज पब्लिकेशन्स। (पेज नंबर 142–145)।

2. अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) (2024) अखिल भारतीय उच्च शिक्षा रिपोर्ट 2021–22 उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। पृष्ठ संख्याः 24–48.

3. कुमार, एम. (2025). Women in Higher Education in India: An Empirical Study- इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्कोप (IRJMS), 4(3) पृष्ठ संख्याः 45–56.

4. कुमार, आर, एवं शर्मा, एस. (2021). ''उच्च शिक्षा में लैंगिंक समानता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020ः एक आलोचनात्मक विश्लेषण''। भारतीय शिक्षा जर्नल, 45(2), (पेज नंबर 78–83)।

5. मंत्रालय, शिक्षा (2024). अखिल भारीतय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) 2022–23 रिपोर्ट। नई दिल्लीः भारत सरकार। (पेज नंबर 45–52)।

6. मिश्रा, आलोक (2020). ''ग्रामीण भारत में बालिकाओं की उच्च शिक्षा की राह में आर्थिक बाधक''। सामाजिक विमर्श पत्रिका, 12(4), (पेज नंबर 102–107)।

7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP). (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020ः एक समावेशी और समतामूलक शिक्षा व्यवस्था, भारत सरकार, नई दिल्ली। पृष्ठ संख्याः 34–42.

8. विश्व बैंक रिपोर्ट. (2023). Tertiary Education Enrolment and Female Labour Force Participation in South Asia- वर्ल्ड बैंक गुप, वाशिंगटन डीसी। पृष्ठ संख्याः 67–89.

9. शर्मा, एम. (2024). Gender Disparity in Enrolment in Higher Education Institutions: Trend Analysis. नेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन, 22(1). पृष्ठ संख्याः 174–182.